(34)

मध्यमवर्गीय कामगार आंदोलन का
अग्रदूत

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स

(कम्यूनवादियों की मजदूर द्रोही हरकतों का भंडा फोड़)

भारतीय मजदूर संघ
2
3-7-70

२
लि
इन्ट
निर्ण

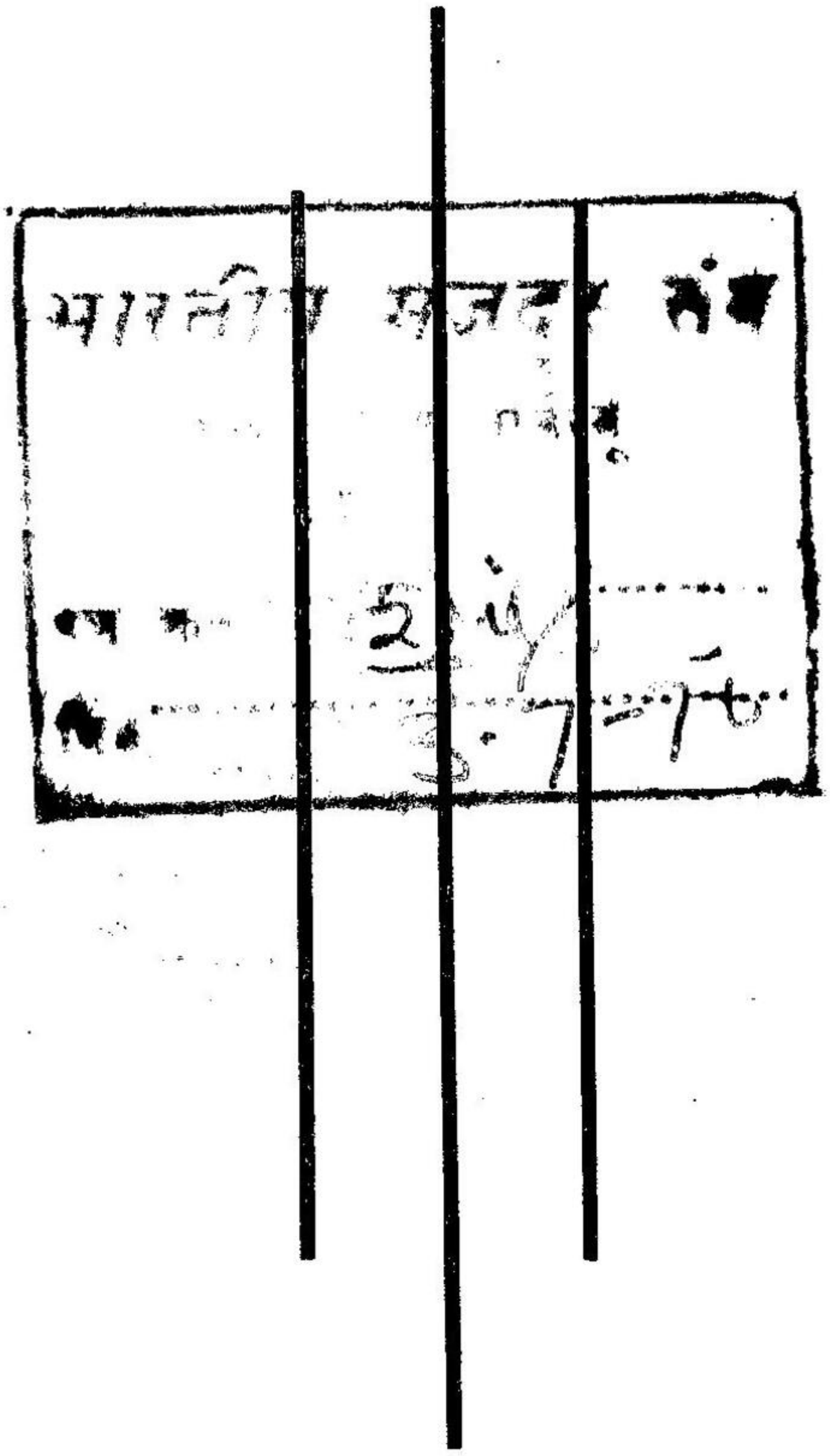

दत्तोपंत ठेंगड़ी

प्रकाशक :

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन

२, नवीन मार्केट, कानपुर

मूल्य : १५ पैसे

मुद्रक :

टिप टाप प्रिन्टर्स

२४/९१, बिरहाना रोड, कानपुर

भारतीय

पत्र क्र.

बैंकिंग उद्योग में काम करने वाले प्रिय बहनों व भाइयो,

आप सबके द्वारा लिये गए बैंक कर्मचारियों के एक राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के पुनीत कार्य के लिए अपना बिना शर्त सहयोग देने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आज के युग में जब राजनीति जीवन के सभीक्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रही है, ऐसे समय आप सब विभिन्न राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों ने राष्ट्रवाद के सर्वमान्य आधार पर एकत्र आने का एक अत्यन्त बुद्धिमत्ता पूर्ण व उत्साहवर्द्धक निर्णय लिया है। प्रजातंत्रीय निर्णय ही आपकी नीति का अंतिम आधार है। बैंकिग उद्योग में विद्यमान यूनियनों को कम्यूनवाद के अमानवीय, राष्ट्रदोही, एवं वर्गवादी कार्य पद्धति से मुक्ति दिलाना आपका पुनीत कर्तव्य है। वास्तव में आप राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रचनात्मक ट्रेड यूनियनवाद के आन्दोलन के मूल स्रोत हैं।

देशभक्त संगठन का उदय

मेरी समझ में इस प्रकार के पुनीत कार्य के लिये अपने को बिना शर्त समर्पण कर देने से बढ़कर अन्य कोई पुनीत कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि नाम और संस्थाओं का कोई उपयोग नहीं जब तक कि वे राष्ट्र को सर्वोपरि न समझें। अतः इस संस्था के राष्ट्रवादी, राजनीतिरहित तथा प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण को देखकर समस्त राष्ट्रवादियों को शतप्रतिशत प्रसन्नता होगी। आपने अपने विधान में यह धारा—कि आप अपने को किसी भी केन्द्रीय श्रमसंगठन से सम्बद्ध नहीं करेंगे या आप कोई राजनीतिक फन्ड नहीं एकत्र करेंगे जोड़ करके एक सुन्दर निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि सभी देश भक्त केन्द्रीय श्रमसंगठन जैसे इन्टक, हिन्द मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, यूटुक आदि भी इस निर्णय का स्वागत करेंगे। आपके संगठन का निमार्ण राष्ट्रवादियों के

मस्तिष्क के उत्तम निश्चय का ज्वलंत प्रमाण है। इसके अतिरिक्त आपको अनेक सार्वजनिक नेताओं--जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, के जो संदेश मिले हैं, उनसे राष्ट्रवादी भारत की भावना का पता चलता है।

मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में सब प्रकार की हिचक और उदासीनता समाप्त हो जावेगी और हमारे देश के हृदयपटल पर एक अत्यन्त देशभक्त श्रमसंगठन का उदय होगा।

कम्यूनवाद बनाम राष्ट्रवाद

निकट भविष्य में आपके सामने काफी ऊंची चढ़ाई का काम आ रहा है। उस समय जबकि सभी देशभक्त तत्व आजादी की लड़ाई में तथा औद्योगिक पुनर्निर्माण में लगे थे, देशद्रोही तत्व श्रम के क्षेत्र में अपने किले बनाने में लगे थे। परिणाम यह हुआ कि वे कुछ अर्थों में इस क्षेत्र में अपने पैर जमा चुके हैं। आपके नये सगठन की अपेक्षा उन्हें कुछ तांत्रिक सुविधायें भी प्राप्त हैं। इस भूमिका में यह हो सकता है कि आपकी प्रगति प्रारम्भ में धीमी मालूम पड़े। मैं समझता हूं कि यह बुराई नहीं बल्कि अच्छाई है। इतिहास आपको सम्मान का स्थान देगा, यदि आपने देशभक्ति के लिए कम्युनिज्म से एवं शैतानी ताकतों से इंच प्रतिइंच टक्कर ली। और आप यह पूरी तरह जान लीजिए कि आपकी प्रत्येक विजय चाहे वह कितनी ही कम महत्व की क्यों न हो, वास्तव में विश्व कम्युनिज्म के लिए ठेस पहुंचाने वाली है। सचमुच आप दुश्मन की मांद में घुसकर लड़ रहे हैं।

कम्युनिष्ट आन्दोलन का राष्ट्रद्रोही स्वभाव आज सिद्ध हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। कम्युनिज्म का सिद्धान्त ही राष्ट्रद्रोही है। इसके अनुसार देशभक्ति "बुर्जुआ" (पूंजीवादी) धारणा है। राष्ट्रवाद के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण मार्क्सवाद व लेनिनवाद के लिये घातक रहा है।

अभी हाल की घटनाओं ने इस सत्य को और भी पुष्ट किया है। जो चीज समय की कसौटी पर खरी उतरी है, उसकी अवहेलना करना निश्चित ही मानसिक गुलामी है।

आलइण्डिया बैंक इम्प्लाइज एसोसियेशन विश्व कम्यूनवाद के आन्दोलन के द्वारा नियंत्रित तथा उसके ही हित के लिए है—यह सत्य है। यह बात भी निष्पक्ष व्यक्तियों को स्पष्ट रहनी चाहिए।

ए० आई० बी० ई० ए० की सदस्यता केवल विकल्प का अभाव

यह सच है कि एक ठोस व प्रभावशाली विकल्प के अभाव में काफ बैंक कर्मचारी अपने स्वार्थों की रक्षा के भाव से इस बात को घोषित करना उचित नहीं समझते कि उनकी यूनियन, जो दिखावटी तौर पर उनकी रक्षा के लिए काम करती है—का नियन्त्रण गद्दारों (देश द्रोहियों) के हाथ मे है। एक बीमार व्यक्ति को अपने शरीर को उस बस्ती में स्थित एकमात्र डाक्टर को मजबूरन सौंप देना पड़ता है, इस बात की परवाह किए बिना—कि उसकी नियत क्या है, उसकी फीस कितनी ज्यादा है। लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है कि कर्मचारियों की रक्षा के लिये केवल एकही प्रतिनिधि (संगठन) होना चाहिए। एन० ओ० बी० डब्ल्यू० बैंक कर्मजारियों के सम्मुख इस अति आवश्यक विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि आपका प्रयत्न सेवा और प्रेम की भावना से ओतप्रोत है इसलिये आप रोगग्रस्त कर्मचारियों के लिए कम्यूनवादी पार्टी के धोखेबाज कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त सलाहकार सिद्ध होंगे।

कम्यूनवाद राष्ट्रद्रोही ही नहीं अपितु मजदूर द्रोही भी

यद्यपि आदतों को खत्म होने में कुछ समय लग सकता है किन्तु धैर्य और सातत्य से जिनका आपके पास पर्याप्त भंडार है आप निश्चित ही अन्धकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि कम्यूनवादी

अपने स्वभाव व नियत से न केवल राष्ट्र द्रोही अपितु मजदूर हितों के भी दुश्मन हैं। उनका निहित स्वार्थ–कर्मचारियों को अज्ञानी और आधा पेट रखने में है। पार्टी के कार्यकर्ता उन कर्मचारियों में एक अन्धी क्रांति के लिये तबतक के लिये एक प्रकार का ईंधन तैयार करते हैं जब तक कि वे कर्मचारी रोटी के एक टुकड़े के लिये कम्यूनवादी पार्टी पर आश्रित नहीं बन जाते। इस लिये जब कभी भी किसी गैर कम्यूनवादी संगठन के द्वारा कर्मचारियों के भाग्य में सुधार लाने की कोई कोशिश की जाती है तो कम्यूनवादियों को यह बात नागवार लगती है और वे नाराज होकर उसे मैदान से बाहर खदेड़ने की कोशिश करते हैं।

ए० आई० बी० ई० ए० का इतिहास इस प्रकार के कर्मचारी विरोधी इरादों से भरा पड़ा है, जो कि कम्यूनवादियों की रण नीति की विशेषता है। यह अनुभव करके कि कर्मचारियों में अपनी जीवन दशा सुधारने के लिये बड़ी जागरूकता है–और यह कि बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण इस भावना की पूर्ति होना भी संभव है, ए० आई० बी० ई० ए० के कम्यूनवादी सदस्यों ने इस बात का प्रयत्न किया है कि श्रमिकों को इसका कम से कम लाभ मिले। बोनस संबन्धी अनेक झगड़ों में इन कम्यूनवादियों ने सभी जगह पर पूंजीपति बैंक मालिक से सांठ गांठ करके कम से कम राशि पर सौदा किया है। यूनियन हाथ में बनी रह सके इस उद्देश्य से उन्होंने समझौता वार्ताओं को काफी देर तक लटकाये रहने का तरीका अपनाया, जिससे कि समय का प्रभाव कर्मचारियों की जीवनी शक्ति पर पड़े और वे मानसिक व शारीरिक दोनों ही से हार करके कुछ तो भी मानने के लिये मजबूर हो जाय, बिना यह जांच किये हुए कि वह "कुछ" उनके पूरे प्राप्तव्य के अनुकूल है या नहीं। यही कारण है कि अनेक ऐसे मसलों में, जो कि औद्योगिक न्यायाधिकरण (Tribunals) और अदालतों के सामने थे, कम्यूनवादी यूनियनों ने आंकड़ो और आर्थिक अंकों के आधार पर, मामलों की योग्यता पर बहस करने से इंकार कर दिया।

नेशनल ट्रिव्यूनल्स (बैंक डिस्प्यूट्स) के सामने, ए० आई० बी०-ई० ए० ने यही नीति अपनाई है। अभी हाल के देसाई एवार्ड में भी तमाम ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि ए० आई०-बी० ई० ए० ने माननीय न्यायाधीश श्री के० टी० देसाई द्वारा कर्मचारियों को मिलने वाला उचित न्याय असम्भव कर दिया। मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उक्त एवार्ड के कुछ उद्धरण आपके सम्मुख पढ़ूंगा।

देसाई एवार्ड के उद्धरण

जीवन निर्देशांक में हुयी वृद्धि के आधार पर कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन सम्बन्धी मामले को प्रस्तुत करने के बाद सम्बन्धित पक्षों में यह मतैक्य हो गया था कि जिस एक बात के आधार पर बैंकिंग उद्योग में वेतन सम्बन्धी विवाद तय होना था वह सर्व साधारण श्रमिकों तथा विशेषत: बैंक कर्मचारियों के उपभोक्ता सामग्री के मूल्य तथा उन कर्मचारियों की उपभोग पद्धति के इर्दगिर्द स्थिति थी। ए० आई० बी०-ई० ए० ने अपना संपूर्ण विवाद इसी आधार पर खड़ा किया था। अत: यह आशा करना स्वाभाविक था कि ए० आई० बी० ई० ए० के प्रतिनिधि पर्याप्त आंकड़ों तथा प्रमाणों के द्वारा अपनी मांग को पुष्ट करने के लिए आगे आते परन्तु इस मसले पर हुये सम्पूर्ण वादविवाद बहस से एक अलग से ही चित्र प्रकट होता है। यहां तक कि प्रारम्भिक सुनवाइयों में जब कि बैंकों के श्रेणी तथा अदालती मामलों के लिये क्षेत्र विभाजन के सम्बन्ध में बहस हो रही थी माननीय न्यायाधीश महोदय एवार्ड के अनुच्छेद ४–१६७ (पृष्ठ–५३) में कहते हैं :—

ऐसे बैंकों की, जिनका प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मेरे सामने हो रहा है–में लगभग १२०० शाखायें हैं। मेरे सामने इन स्थानों के सम्बन्ध में कोई भी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनके द्वारा इन स्थानों के जीवन यापक मूल्य, जीवन स्तर तथा उपभोग पद्धति के आधार पर

इनके श्रेणी विभाजन में मुझे सहायता मिली होती। वास्तव में मैंने सम्बन्धित पार्टियों से अनेक बार उक्त प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करने के लिये इच्छा व्यक्त की किन्तु कोई भी मान्य सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी। अगर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध हुई होती तो चीजों पर दूसरे ही ढंग से विचार होता अपेक्षाकृत वर्तमान स्थिति के जिसे हम कभी "एक निर्जीव सूत्र का अन्धा व्यवहार" की संज्ञा देते हैं।

मैं यह बात समझ सकता था कि ए० आई० बी० ई० ए० ऐसी कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत कर सकती थी जिससे बैंक मालिकान का मतैक्य होता किन्तु मैं यह नहीं मान सकता हूं कि एक यूनियन, जो कि जीवन यापक आंकड़ों. जीवन स्तर तथा उपभोग पद्धति के आधार पर अपनी मांग प्रस्तुत करने के बाद भी अपनी मांगों को पुष्ट करने के लिये कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं प्रस्तुत करती और न्यायाधीश को "एक निर्जीव सूत्र का अन्धा व्यवहार" की घोषणा करने की छूट दे देती है।

इसी प्रकार अनुच्छेद ५–१०१ (पृष्ठ ९७) में भी न्यूनतम व अधिकतम वेतन क्रम के अनुपात के विषय में वहस करते हुए विद्वान न्यायाधीश महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि "क्लर्क तथा सबार्डिनेट स्टाफ के वेतन क्रमों के न्यूनतम व अधिकतम के बीच सुझाये गये सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक या तर्क संगत कारण नहीं दिया गया है।" कम्यूनवादियों की इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण पैंकिग उद्योग के सिपाहियों (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों) को बहुत बड़ी हानि पहुंची है।

परिणामतः नया वेतन क्रम देते समय विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद ५–१९३ पृष्ठ ११९ में बहुत ही महत्वपूर्ण टीका की है। मेरे सम्मुख पिछले ट्रिव्यूनल्स के निर्णयों की बड़ी जोरदार आलोचना की गई है कि वे (निर्णय) पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में दिये गये हैं। यहां तक कि अपनाये गये सिद्धान्तों पर भी आपत्ति की गई है। मेरे सम्मुख जो भी विश्वसनीय समझे जाने वाले आंकड़े हैं और जिन पर देश के विभिन्न

भागों में स्थित बैंक के कार्यालयों के क्लर्क तथा सबार्डनेट स्टाफ के कर्मचारियों के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में निर्णय आधारित किया जा सकता है वह अत्यल्प है यहां तक कि देश के विभिन्न भागों में जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र और मकान की कीमतों के सम्बन्ध में भी मुश्किल से ही कोई विश्वसनीय प्रमाण है। जब वेतन क्रमों का गठन किसी आधार वर्ष (Base Year) से सम्बन्धित होना है तो कर्मचारियों की आवश्यकताओं को उक्त आधारवर्ष तथा दिये जाने वाले (नये) वेतन के प्रकार को ध्यान में रखकर विचार करना उचित होगा। इस प्रकार का वेतन क्रम निश्चित करने के बाद आधार वर्ष के स्तर में ऊपर होने वाले परिवर्तन (वृद्धि) के मुकाबले में मंहगाई भत्ता के भुगतात का एक सूत्र सामने लाना होगा। दुर्भाग्य से मेरे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने द्वारा उल्लिखित आधार वर्ष के अनुरूप कर्मचारियों की, रुपयों की सकल में, आवश्यकताओं के आधार पर वेतन क्रमों की रचना कर सकता।" और अब आगे आने वाली राष्ट्रीय त्रिदलीयवार्ता में कम्यूनवादी राजनीतिक घोषणा व श्रमिक विरोधी नीति को कार्यान्वित करने में लगे हैं। यह बात उनके मांगपत्र को देखने से भी पता चल सकती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ए० आई० बी० ई० ए०

ए० आई० बी० ई० ए० की एक मांग अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (श्रमिक वर्ग के लिए) की जांच करने तथा मंहगाई भत्ते में तदनुकूल सुधार लाने की है। यह सर्वविदित है कि अखिल भारतीय सूचकांक लगभग विगत ४० वर्षों से गलत आधार पर संग्रहीत किया जा रहा है और कम मंहगाई भत्ते के रूप में कर्मचारियों के साथ अन्याय करता रहा है। किन्तु कम्यूनवादियों ने जो कि इस श्रमिक क्षेत्र में पिछले ४० वर्षों से सक्रिय रहे हैं, कभी भी सूचकांकों के इस दोष

पूर्ण एवं श्रम विरोधी गठन की ओर उंगली नहीं उठायी। १८ वीं शताब्दी की दकियानूसी कम्यूनवादी पार्टी की आंख तो तब खुली जब कि भारतीय मजदूर संघ की बम्बई शाखा ने १५ अप्रैल १९६३ से २० अगस्त १९६३ तक किये गये अपने निरन्तर आन्दोलन के द्वारा बम्बई की तथा कथित अत्यन्त वैज्ञानिक सूचकांक को बुरी तरह रद्द सिद्ध कर दिया।

किन्तु फिरभी ए० आई० बी० ई० ए० के ये ओछे लोग जानबूझ कर बैंक कर्मचारियों के लिये श्रमिक वर्गीय सूचकांक (Working Class Index) की रट लगा रहे हैं जबकि इन बैंक कर्मचारियों के लिये वास्तव में मध्यम वर्गीय सूचकांक (Middle Class Index) अधिक व्यवहार्य है। देसाई एवार्ड के अनुच्छेद ५-६५ (पृष्ठ ८८) के द्वारा बैंक कर्मचारियों के लिए मध्यम वर्गीय मूल्य सूचकांक के अनुकूल लाभ एवं सुरक्षा की मांग करने के लिये अग्रिम तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। ऊक्त अनुच्छेद के अनुसार "जनता के किसी वशिष्ट वर्ग के जीवन यापक मूल्यों में हुई वृद्धि को निश्चित करने के लिये उचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का होना आवश्यक है। वर्तमान अखिल भारतीय श्रमिक वर्गीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का गठन केवल फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की दृष्टि से बनाया जाता है। उसी प्रकार का ऐसा कोई अखिल भारतीय सूचकांक उस मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नहीं है जिसकी श्रेणी से बैंकिंग उद्योग में लगे हुए क्लर्क स्टाफ मुख्यतया आते हैं।"

अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यकी संगठनों की तात्रिक समितियों (Technical Communities of International Statistical Bodies) ने बारम्बार कृषक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, तथा मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के लिये (अलग २) कम से कम त्रिपक्षीय जीवन मूल्य सूचकांकों की अवश्यकता की वकालत की है। भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यकी संगठन (Central Statistical Organisation) ने अपने वृत्त १९५८-५९ के प्राक्कथन के अनुच्छेद ४ में कहा है--

"केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन निश्चित करने तथा ताल-मेल बिठाने के सिलसिले में अनेक बार–अखिल भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन मूल्य सूचकांक की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। अतएव श्रम एवं नियोजन मन्त्रालय द्वारा जीवन मूल्य सूचकांकों के विषय पर स्थापित तांत्रिक सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee) ने १९५४ में यह अनुशंसा की कि पारिवारिक वजट की जांच की जाय जिसमें अन्य वर्गों के साथ ही शहरी मध्यम वर्गीय आबादी भी हो। १९५७ में समाचार पत्र कर्मचारियों के लिये गठित वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इगित करते हुए उल्लेख किया कि मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए व्यवहार्य जीवन मूल्य सूचकांकों के अभाव में इस (आयोग) को अपने कार्य में बहुत सी रुकावटें आई और अनुशंसा की कि चूंकि मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित विवादों की संख्या में वृद्धि हो रही है, सरकार को चाहिये कि विश्वसनीय मध्यम-वर्गीय, जीवन मूल्य सूचकांकों के संग्रह तथा प्रकाशन हेतु आवश्यक कदम उठाये।"

मध्यम वर्गीय सूचकांक व बैंक कर्मचारी

सच्ची बातें तर्कों से भी अधिक बुलन्द होती हैं। कम्यूनवादी एक ओर तो बढ़ते हुये मूल्य स्तर के विरोध में चिल्लाते हैं किन्तु दूसरी ओर वे एक ऐसी योजना की वकालत करते हैं जिसके फलस्वरूप ही उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वे जीवन मूल्य सूचकांक के दोष पूर्ण गठन के सम्बन्ध में चुप्पी साधकर उसके भागीदार बन जाते हैं जिसके ही आधार पर वेतन के ऊपर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को निष्क्रिय करने का सारा तंत्र ही खड़ा हुआ है। ट्रिव्यूनल्स के सामने अपने सभी तर्कों में ये कम्यूनवादी ऐसा कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करते जिससे कि कर्मचारियों को न्याय मिल सके। जब श्रमिकों में उत्पन्न क्षोभ की ताकत के सामने उन्हें मूल्य सूचकांक के विषय को टालने में कठिनाई का अनुभव होता है उस समय वे मध्यम वर्गीय मूल्यसूचकांक के

स्थान पर श्रमिक वर्गीय मूल्य सूचकांक मांग कर चीजों को आपस में उलझा देते हैं। सांख्यिकी व्यवहार के सभी विद्यार्थियों को यह भली भांति पता है कि मध्यम वर्गीय जीवन मूल्य सूचकांक का व्यवहार बैंक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपयोक्ता मूल्य सूचकांक को शुद्ध करने के अतिरिक्त न केवल अधिक लाभदायक है अपितु इससे भी आगे वह अन्य की अपेक्षा शीघ्रता से किया जा सकता है। मध्यम वर्गीय जीवन मूल्य सूचकांक सम्बन्धी प्रमाण व आंकड़े तैयार हैं और यह केवल एक महीने की बात है कि इस आंकड़े को उपयोग में लाया जा सकता है। इसके विपरीत अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग जीवन मूल्य सूचकांक को शुद्ध करना तब तक प्रशासकीय दृष्टि से असम्भव है जब तक की १९६८-६९ की जांच एक रूप से संपूर्ण राज्यों में पूर्ण नहीं हो जाती।

मध्यम वर्गीय मूल्य सूचकांक और विशेषज्ञों की राय

अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय भी बैंक कर्मचारियों द्वारा मध्यम-वर्गीय मूल्य सूचकांक की मांग के पक्ष में है। जीवन यापक मूल्य के ऊपर विचार करने के लिये नियुक्त भारत सरकार की तांत्रिक सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee) भी उन बैंक कर्मचारियों के पक्ष का समर्थन करती है। विभिन्न ट्रिव्यूनल्स जिसमें देसाइ ट्रिव्यूनल भी सम्मिलित है—का कहना है कि मध्यम वर्गीय सूचकांक के आधार पर ही बैंक कर्मचारियों के साथ न्याय किया जा सकता है। देश के केन्द्रीय साख्यिकी संगठन ने इस प्रकार के न्याय दिये जाने की समर्थता प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण आंकड़ों सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है परन्तु यह सब होते भी ए० आई० बी० ई० ए० के नियन्त्रक श्रमिक विरोधी कम्यूनवादियों ने इस प्रकार की मांग करने से इन्कार कर दिया है। यदि बैंक कर्मचारियों का संगठन ही मध्यम वर्ग की समस्याओं पर एक शब्द नहीं बोलता तो फिर उन मध्यम वर्ग के लोगों की मांगों को लेकर कौन चलेगा ?

वर्ग संघर्ष और कर्म विहीन समाज की कल्पना ढकोसला मात्र

यह सम्भव है कि कुछ लोग वर्ग विहीन समाज के नाम पर मध्यम वर्गीय मूल्य सूचकांक की खिल्ली उड़ायें। इस प्रकार के प्रयत्नों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार्क्सवादियों ने भी समाज को सम्पत्ति सहित तथा सम्पत्ति रहित इन दो वर्गों में विभाजित किया है। कम्यूनवादी रूस और चीन में समाज के भीतर का यह श्रेणी विभाजन पूंजी वादी अमेरिका अथवा पश्चिमी जर्मनी की अपेक्षा कहीं दस गुना असमान है। वैज्ञानिक श्रेणी विभाजन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लोगों के वेतन की विषमता का क्या आधार होना चाहिए–यह एक स्वतन्त्र शोध का विषय है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस विषय पर प्राचीन भारतियों के विचार भी अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील, श्रेष्ठ तथा वैज्ञानिक थे। कुछ भी हो मध्यम वर्गीय जीवन मूल्य सूचकांक का सिद्धांत समाज के अन्दर के श्रेणी विभाजन से सम्बद्ध है और इस सम्बद्ध में वर्गविहीनतावाद की कोई उपयुक्तता नहीं है ! इतिहास में ऐसे किसी समाज का पता नहीं चलता है कि जो श्रेणी रहित हो और आज के औद्योगिक और गतिमान समाज में वर्तमान विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं के मूल्य मापक यन्त्र अर्थात् जीवन मूल्य सूचकांक की अवहेलना करके कोई आर्थिक न्याय भी नहीं किया जा सकता। मध्यम वर्गीय जीवन मूल्य सूचकाँक तथा उस सूचकांक का असली वेतन के रूप में शत प्रतिशत श्रेणी विभाजन बैंक कर्मचारी आन्दोलन के लिये अपरिहार्य है। इस प्रकार की मागों को लेकर चलने से इंकार करने वाले ए०आई०बी०ई०ए० के कम्यूनवादी बैंक कर्मचारियों के लिये कम से कम पर समझौता करने की अपनी पुरानी चाल खेल रहे हैं और उन बैंक कर्मचारियों के आन्दोलन को गरीब मजदूर वर्ग के नाम पर देश द्रोही क्रान्ति जो वे करने वाले हैं की ताप का इंधन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह अच्छा मौका है कि राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित मजदूर संगठनों के संचालन में कम्यूनवादियों की इन चालों का पूरी तौर पर भंडा फोड़ किया जाय।

हास्यास्पद शोषण

ऐसे उदाहरण जिसमें कम्यूनवादियों ने बैंक कर्मचारियों का शोषण किया है सचमुच में हास्यास्पद हैं। "समान कार्य के लिये समान वेतन" एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसकी घोषणा वर्कर्स आर्गबाइजेशन ने बड़े जोरों से की है। एक असमान वेतन राशि (Pay Packet) जिससे देश के विभिन्न अंचलों में समान उपभोग्य सामग्रीव सेवायें उपलब्ध की जा सकती हैं ——यह मांगों को पूरा कराने का स्वाभाविक तरीका है। किन्तु कम्यून वादियों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने आवादी के आधार पर भत्ते मांग कर इस समस्या को हल कर लिया है। इस वास्तविकता के अलावा कि किसी विशेष संख्या पर ही उदाहरणार्थ ७ लाख पर न कि ५ लाख पर आबादी को बिभाजित करने के पीछे कोई तर्क नहीं है, साथ ही विभिन्न अंचलों के लिये विभिन्न भत्ते की मांग के औचित्य से भी आबादी का आधार निरर्थक है। क्या इसको इस तरह कहा जाय कि यदि अपने शहर के लिये अधिक भत्ते प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे आबादी वढ़ाने का प्रचार करना चाहिये और हमें परिवार नियोजन केन्द्रों पर मोर्चा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे भत्ते में कमी हो रही है। यह तर्क का मजाक उड़ाना है। भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने विभिन्न नगरों की तुलनात्मक महंगाई के आंकड़े प्रकाशित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की हैं। वास्तव में ये वे आंकड़े हैं जो कि विभिन्न नगरों की आर्थिक मांग की दृष्टि से उपयुक्त हैं, न कि आबादी की संख्या। श्रमिक विरोधी ए० आई० बी० ई० ए० इस वस्तु स्थिति को छिपा करके रखना चाहती है।

मैं इस बात का संकेत तो कर ही चुका हूं कि ए०आई०बी०ई०ए० न्यूनतम व अधिकतम वेतन की दूरी से सम्बन्धित कोई भी आंकड़ा नहीं प्रस्तुत करना चाहती है। यह (ए० आई० बी० ई० ए०) अपने इस विचार को कि एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी के सामान्य परिवार में केवल ३ सदस्य होते हैं—की रट लगाती है जब कि मध्यम वर्गीय सर्वेक्षण

के अनुसार औसत परिवार के सदस्यों की संख्या ६ है। यह (ए० आई० बी० ई०ए०) वैज्ञानिक पदोन्नति नीति (Scientific Promotion Policy) निर्धारण सम्बन्धी संसार में एकत्रित समस्त अनुभवों की अवहेलना करना चाहती है। यह बैंकों के श्रमिकीकरण का विरोध करती है और चाहती है कि बैंक कर्मचारी एक निर्जीव नीरस सरकारी उद्योग का एक अग तथा सरकारी यंत्र का एक गुलाम मात्र बन जाय जिससे कि वह भी जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की भांति आटोमेशन के कारण उत्पन्न छंटनी के एक मात्र विकल्प को अथवा कम वेतन राशि स्वीकार करने के लिए विवश हो जाय। ए० आई० वी० ई० ए० की पूरी पंक्ति की पंक्ति मजदूरों की नम्बर एक की दुश्मन है।

न्यूनतम व अधिकतम का ताल मेल

अभी हाल में भारत सरकार ने योजना आयोग में 'आय एवं जीवनस्तर विभाजन समिति' (Committee on Distribution of Income and Levels of Living) की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट का एक मात्र उद्देश्य आर्थिक सम्पत्ति के खपत के तरीकों के द्वारा स्वतन्त्र और समानता पूर्ण सामाजिक मनोवृत्ति व उसके जीवन मूल्यों का निर्माण करना है। कुछ श्रम–अर्ध शास्त्रियों ने अब यह अनुमान लगाया है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति को इस प्रकार बांटा जाना है कि विभिन्न वेतन राशियां १८० रु० की न्यूनतम व १८०० रुपये की अधिकतम दूरी के बीच श्रेणियों में बैठ जांय जिससे कि १ व १० के अनुपात वाली न्यूनतम व अधिकतम आर्थिक लाभ के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके ! मध्यम वर्गीय सर्वेक्षण द्वारा प्रदर्शित मध्यम वर्गीय परिवार की आदर्श व्यय पद्धति (Model Expenditure Pattern) के अनुसार एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार को देश के शिक्षित समाज के लिये अपेक्षित स्तर पर किसी प्रकार जिन्दा रखने के लिये प्रति मास ३५०) की आवश्यकता है। देश के उत्थान के लिये आवश्यक है कि

मध्यम वर्ग के लोग विभिन्न आन्दोलनों उदाहरणार्थ – सहकारिता, मजदूर संगठन, साक्षरता अभियान, भारत सेवक समाज, राष्ट्रीय एकता आन्दोलन आदि के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भाग लें। इन कर्मचारियों के बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न सामाजिक व शैक्षणिक कार्यों जैसे एन० सी० सी०, अध्ययन यात्रा, प्राविधिक शिक्षण योजनायें आदि में भाग लें। केवल इसी उद्देश्य से सरकार की विभिन्न समितियों ने मध्यम वर्ग की, जो कि समाज की रीढ़ हैं–के सामरिक महत्व की घोषणा की है। यदि मध्यम वर्ग को इन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी है तो एक औसत बैंक क्लर्क (जो कि मध्यम वर्गीय आन्दोलन की महत्वपूर्ण कड़ी है) की वेतन लम्बान (Pay range) ३५० रुपये से ८०० रुपये प्रति मास होनी चाहिए और इस वेतन लम्बान में को १८० रु० से १८०० रु० तक की राष्ट्रीय वेतन लम्बान में उचित रीति से बैठाया जाय, जिसमें इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी समानुपातिक वेतन क्रम मिल सके।

बैंकों का स्वामित्व बैंक कर्मचारियों का

इस प्रकार के कुछ सत्य हैं जिनसे एक मध्यम वर्गीय संगठन के नाते आपको भिड़ना होगा। राष्ट्रीय अर्थ तन्त्र में अपने लिए इस प्रकार के स्थान पाने का प्रयत्न बैंकों की व्यवस्था में साझेदारी अथवा उनके पूर्ण नियन्त्रण की दृष्टि से भी आपको सिद्धता प्राप्त करनी चाहिए। बैंकों का संचालन इस ढंग से होना चाहिए कि उसके द्वारा न केवल हमारी मांग के अनुसार योग्य न्याय प्राप्त हो अपितु साथ ही वे बैंकिंग उद्योग के अपने उत्तरदायित्व, अर्थात् वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने न देना तथा पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने का योग्य निर्वाह कर सकें। यह इस उद्योग के लिये राष्ट्रीय अनुशासन है, जो कि हमारी मांग का एक अंग है। यदि पूंजीपति वर्ग इस कर्त्तव्य के पालन करने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें चाहिए कि वे बैंकों का स्वामित्व छोड़ दें

और इच्छुक कर्मचारियों को भारत के बैंकिंग उद्योग की व्यवस्था व उसका स्वामित्व लेने की अनुमति दें।

शुभकामना

मुझे भरोसा है कि नव निर्मित एन. ओ. बी. डबल्यू. उपर्युक्त सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बैंक कर्मचारियों को योग्य नेतृत्व प्रदान करेगा।

इस आशा और विश्वास के साथ मैं इस नवीन संगठन की सफलता की कामना करता हूं।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स बैंक कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय मोर्चा है, जहां समस्त राष्ट्रवादी बैंक कर्मचारी एकत्र आकर सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति पाने के लिये संघर्षशील हो सकते हैं। नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स न तो वर्ग वाद में विश्वास करता है, न ही उसे बढ़ावा देना चाहता है। जिस भी ढंग व पद्धति से कर्मचारियों, व निजी उद्योग तथा देश का हित हो, वही "आर्गनाइ-जेशन" के काम करने का रास्ता है। चूँकि' 'आर्गनाइजेशन"वर्ग विद्वेष का हामी नहीं है। अतः कभी कभी लोग उसे प्रोमैनेजमेंट (मालिकपरस्त) होने का भ्रम पैदा करते हैं परन्तु सच बात यह है कि आर्गनाइजेशन ,प्रोमैनेजमेंट' नहीं अपितु" प्रोइण्डस्ट्री', (उद्योगपरस्त) है।

—o—